take into account sub-district level requirements. To enable the States to prepare district plans, central assistance is provided under the scheme of strengthening of planning machinery. The Plan proposals developed by District Planning Boards are suitably incorporated in the Annual Plan proposals of State Governments which in turn are discussed in the Annual Plan meets of the Planning Commission.

Annual Plan for Orissa Government

1362. SHRIMATI ILA PANDA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) what is the outlay proposed by the Orissa Government for the State's annual ph:n for 1994-95;

(b) what is the otlay approved by the Planning Commission;

(c) what is the Central aassistance for this annual plan ; and

(d) what are the main schemes included in the annual plan, along with the proposed outlays ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) In view of non-finalisation of resources for 1994-95, no outlay for Annual Plan 1994-95 has been proposed by the Orissa Government.

(b) to (d) Do not arise.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों का रहन सहन का स्तर

1363. **श्रीमति सत्या बहिन** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिये चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शुरु की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त योजनाओं की समीक्षा की गई है ;

(ग) अनुसूचित जातियों के लिये बनाये गये कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पेश आ रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का जीवन स्तर सुधारने हेतु रोजगार और आय सृजन के लिये चालू पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एस एस एफ डी सी) राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम (एस सी डी सी) और जनजातीय सहकारी मार्केटिंग विकास फेडरेशन (ट्राईफेड) के माध्यम से प्रभावी स्कीमें क्रियान्वित की जाती हैं ।

(ख) जी, हां, । इन निगमों द्वारा क्रियान्वित स्कीमों की विभिन्न समितियों, नामतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनजातीय सलाहकार परिषद् और अन्य राज्य स्तरीय समितियों द्वारा समय-समय पर समीक्षा की गई है ।

(ग) इन स्कीमों के क्रियान्वयन में आ रही मुख्य समस्याएं विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी लाभग्रहियों की पहचान की समस्या और स्कीमों का आवर्ती मूल्यांकन की है ।

(घ) क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार लाने की आवश्यकता के लिये राज्य सरकार पर जोर डालते हुए बेहतर समन्वय की कोशिशें की जा रही हैं ।